अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की जद्दोजहद

कोविड की घातक दूसरी लहर झेलने के बावजूद कोविड पूर्व के स्तर से आगे बढ़ी अर्थव्यवस्था

2020-21 में 5,12,860 करोड़ का बजट 3,87,710 करोड़ खर्च में सिमट गया था

2021-22 का खर्च 4,84,542 करोड़ रुपये पार करने की उम्मीद

महेंद्र तिवारी

वर्ष 2020 कोरोना महामारी से अर्थव्यवस्था को सदी की सबसे बड़ी चोट देने का साल था तो 2021 कोविड की दूसरी लहर का घातक दंश सहने के बावजूद पटरी पर आने की जद्दोजहद में जुटा रहा। कोविड की संभावित तीसरी लहर का खास असर न पड़ा तो नए साल में अर्थव्यवस्था तेज रफ्तार पकड़ सकती है।

वर्ष 2020-21 में सारे बजट अनुमान बेपटरी हो गए थे। वजह, वर्ष 2020 में 22 मार्च से लॉकडाउन के एलान से पहले 18 फरवरी 2020 को यूपी का बजट पेश किया जा चुका था। तब तक अर्थव्यवस्था अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी और उसी लिहाज से ग्रोथ के अनुमान लगाए गए थे। मगर, करीब ढाई महीनों लंबे लॉकडाउन का असर ये हुआ कि औद्योगिक व सर्विस सेक्टर की गतिविधि पूरी तरह ठप हो गई। लुंज-पुंज पड़े हेल्थ सेक्टर को खड़ा करने में पूरा फोकस लग देना पड़ा। श्रमिकों व गरीबों की मदद के लिए सरकार को कई पैकेज घोषित करने पड़े। अनाज और आर्थिक सहायता जारी करनी पड़ी। नतीजा ये हुआ कि सरकार की राजस्व प्राप्तियां अनुमान के मुकाबले करीब 30 फीसदी गिर गईं। अनुमान से 6.33 फीसदी अधिक ऋण लेना पड़ा। खर्चों में अप्रत्याशित रूप से करीब 25 फीसदी की वृद्धि हुई। इसका परिणाम यह हुआ कि वित्त वर्ष 2020-21 में 5,12,860.72 करोड़ का जो बजट पेश हुआ था, उसका वास्तविक आकार 3,87,710.67 करोड़ पर सिमट गया। यह दो वित्त वर्ष पूर्व 2018-19 के वास्तविक बजट खर्च 3,91,210.62 करोड़ से भी 12,499.95 करोड़ रुपये कम है। इसी तरह का असर राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) पर पड़ा। मगर, उल्लेखनीय प्रदर्शन कृषि सेक्टर का रहा। वर्षों से उपेक्षित कृषि सेक्टर रीढ़ ताने खड़ा रहा और अर्थव्यवस्था की गिरावट को संभाले रहा। 2021 में आम जनजीवन सामान्य होकर आर्थिक गतिविधियां पटरी पर आ ही रही थी, कि कोविड की दूसरी लहर ने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। हजारों लोगों की मौत हो गई। ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने की कोशिश और कठिन हो गई थी।

मगर, ताजा अनुमान बता रहे हैं कि अर्थव्यवस्था कोविड पूर्व स्तर पर अभी पहुंच नहीं पाई है। पर, पूर्व स्तर पाने के लिए सकारात्मक वृद्धि के साथ आगे बढ़ रही है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए पेश अंतरिम बजट में पुनर्रीक्षित अनुमान लगाया गया है कि वित्त वर्ष 2021-22 का बजट खर्च 4,84,542 करोड़ रुपये पार कर जाएगा। यह 2019-20 के बजट अनुमान 4,79,701 करोड़ और वास्तविक खर्च 3,83,352 करोड़ से ज्यादा है। विशेषज्ञों का कहना है कि अर्थव्यवस्था बेहतरी का संकेत कर रही है। बेरोजगारी दर सुधरी है। मानसून बेहतर रहने से कृषि उत्पादन के बेहतर रहने के संकेत हैं। इससे वित्त वर्ष के वास्तविक आंकड़े आने पर रिकवरी व तेज ग्रोथ साफ नजर आएगी।

कोविड का असर व उससे उबरने की कोशिश

वित्त वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक बजट खर्च	गत वर्ष की अपेक्षा वास्तविक खर्च में वृद्धि/कमी
2017-18	3,84,660	3,21,823	सामान्य वर्ष .....
2018-19	4,28,385	3,91,211	सामान्य वर्ष 70612 करोड़ ज्यादा
2019-20	4,79,701	3,83,352	कोविड शुरू, मार्च से लॉकडाउन 7859 करोड़ कम खर्च
2020-21	5,12,861	3,78,710	कोविड काल पूर्ण असर 4642 करोड़ कम खर्च
2021-22	5,50,271	4,84,542	(अनंतिम) दूसरी लहर लेकिन आर्थिक गतिविधि सामान्य 1,05,832 करोड़ ज्यादा का अनुमान

नोट- आंकड़े करोड़ रुपये में हैं।

सरकार खर्च को तरस गई

अर्थव्यवस्था की बदहाली का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि जिस सरकार ने स्थिति सामान्य रहने पर पहले वर्ष 2017-18 की अपेक्षा 70 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च किया था, बाद के वर्षों में उससे कम में सिमट गई। 2018-19 में खर्च बजट के बराबर भी वह किसी वित्त वर्ष में नहीं खर्च कर पाई। चालू वित्त वर्ष में इसमें प्रगति के संकेत हैं।

अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के इन प्रयासों का दिखा असर

- नौकरियों की भर्ती तेज की गई और प्राइवेट सेक्टर को कई सहूलियतें व प्रोत्साहन दिए गए।
- खर्चों में कटौती की गई और टुकड़ों में राशि जारी की गई।
- मुफ्त कोविड टीकाकरण का अभियान छेड़ा गया, जिससे लोगों के आत्मविश्वास की बहाली हुई और वे काम के लिए बाहर निकले।
- राजस्व वसूली बढ़ाने का प्रयास हुआ।
- केंद्र से स्वीकृत अतिरिक्त ऋण सीमा का उपयोग कर अर्थव्यवस्था में डालने का काम हुआ।
- इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को भरपूर समर्थन दिया गया। सड़क-बिजली के साथ-साथ एक्सप्रेस वे, एयरपोर्ट व मेट्रो के काम को रफ्तार दिया गया।
- एमएसएमई सेक्टर को ऋण दिलाने का विशेष प्रयास हुआ, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का फ्लो बना।
- स्थिति नियंत्रण में आने के बाद कर्मचारियों के महंगाई भत्ते व बोनस बहाल किए गए और बड़े डीए की भी मंजूरी दी गई।
- किसानों को किसान सम्मान निधि की योजना समवाल साबित हुई। पूरी अवधि किसानों को यह राशि तय अंतराल पर मिलती रही। इससे किसान का काम चलता रहा और मुश्किल दौर में अर्थव्यवस्था के लिए कृषि ही सबसे मददगार साबित हुई।

अर्थव्यवस्था पकड़ रही रफ्तार

अर्थशास्त्री प्रोफेसर एपी तिवारी कहते हैं कि जीएसटी कलेक्शन, रोजगार की दर व जीएसडीपी के त्वरित अनुमान के संकेतों से साफ है कि 2021-22 में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के प्रयास सफल रहे हैं। रोजगार की दर में वृद्धि हो रही है। वह बताते हैं कि कोविड की दूसरी लहर आने पर इंडस्ट्री को चलाए रखने का निर्णय, संयोग से किसानों को किसान सम्मान निधि के रूप में महामारी से पहले महत्वपूर्ण समर्थन और किसानों को लगातार किस्तों का भुगतान, पलायन कर लौटे मजदूरों को ओडीओपी योजना व मनरेगा के जरिए स्थानीय स्तर पर रोजगार दिलाने की कोशिश व भिन्न-भिन्न योजनाओं व परियोजनाओं के जरिए गरीब व श्रमिक वर्ग को लगातार राशन या आर्थिक सहयोग से ठप पड़ी अर्थव्यवस्था चल पड़ी और अब यह रफ्तार पकड़ रही है। नए वित्त वर्ष में यह तेज ग्रोथ दिखा सकती है।

रिकवरी की राह पर यूपी की अर्थव्यवस्था

मुख्य संकेत	जीएसडीपी वृद्धि
2020-21	पहली तिमाही ऋणात्मक 22.5 प्रतिशत
2021-22	पहली तिमाही 19.6 प्रतिशत

जीएसडीपी राशि

पहली तिमाही 2019-20	257639.79 करोड़
पहली तिमाही 2020-21	192896.17 करोड़
पहली तिमाही 2021-22	230673.02 करोड़

कोविड की वजह से 2020-21 में जीएसडीपी में 5.9 प्रतिशत की कमी आई।

2021- 22 की पहली तिमाही की जीएसडीपी रकम 230673.02 करोड़, 2019-20 की पहली तिमाही की 257639.79 करोड़ से अभी कम है। पर, सारे पैरामीटर संकेत कर रहे हैं कि रिकवरी तेज हो रही है।

2020-21 पहली तिमाही संकुचन दर

(अप्रैल से जून 2020) लॉकडाउन अवधि

प्राथमिक क्षेत्र	4.5 प्रतिशत
द्वितीयक क्षेत्र	42.9 प्रतिशत
तृतीयक क्षेत्र	22.8 प्रतिशत

2021-22 पहली तिमाही में रिकवरी

प्राथमिक क्षेत्र	5.8 प्रतिशत
द्वितीयक क्षेत्र	40.9 प्रतिशत
तृतीयक क्षेत्र	16.3 प्रतिशत

यूपी की बेरोजगारी दर

नवंबर 2018	6.7 प्रतिशत
नवंबर 2019	8.1 प्रतिशत
नवंबर 2020	5.2 प्रतिशत
नवंबर 2021	4.8 प्रतिशत

स्रोत : सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनोमी
जीएसडीपी से संबंधित आंकड़ों का स्रोत : राज्य नियोजन संस्थान (अर्थ एवं संख्या प्रभाग)

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर सरकार की पूरी टीम इस प्रयास में लगी रही कि इंडस्ट्री बंद न हो।

दूसरी लहर में इंडस्ट्री को बंद नहीं होने दिया गया। इसका असर यह हुआ कि अर्थव्यवस्था तेजी से उठी है। हालांकि, होटल, रेस्टोरेंट व हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री अभी ठीक से आगे नहीं बढ़ पा रही है। दूसरा, कच्चे माल के दाम तेजी से बढ़े हैं। यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि यह स्थिति क्यों बार-बार पैदा हो रही है। खाद्य तेल, स्टील व सीमेंट जैसे वस्तुओं के दाम में वृद्धि हुई है। इस ओर ध्यान दिए जाने की जरूरत है।

- सीपी गुप्ता, चेयरमैन सीआईआई यूपी

अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है, लेकिन अभी कोविड पूर्व स्तर प्राप्त करने में समय लगेगा। प्रिंट व पैकेजिंग इंडस्ट्री कोविड पूर्व की तुलना में 30% ही है। ऑटो मोबाइल इंडस्ट्री भी रफ्तार पाने के लिए संघर्ष कर रही है। हालांकि, मेडिकल व फूड इंडस्ट्री ने तेज प्रगति की है। कोविड स्तर पार करने में अभी समय लगेगा। **- एसपी शर्मा,** पूर्व राष्ट्रीय सचिव आईआईए